बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 24 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 31 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली में बढ़ता कार क्लोनिंग रैकेट- चोरी, नकली कागजात और डिजिटल धोखाधड़ी का नया खेल

नई दिल्ली । दिल्ली में कार चोरी का एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें पुराने जमाने की चोरी के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का तड़का लगा है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो गाड़ियां चुराकर उनके नकली कागजात बनाता था, असली वाहनों की पहचान क्लोन करता था और फिर इन कारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डीलरों के जरिए बेच देता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच तब शुरू की जब एक प्रीओन्ड (सेकंड हैंड) कार कंपनी ने अपनी टेक-ड्रिवन सेलिंग प्लेटफॉर्म पर पांच संदिग्ध ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट की। कंपनी की जांच में पता चला कि तीन कारें उनके रिटेल सेंटर में मिलीं और दो अन्य पार्टनर डीलरों के पास बेची गईं, जो किसी नकली कागजात के साथ थीं।

वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए एनडीएमसी ने दोगुना किया पार्किंग शुल्क, ग्रेप 2 के तहत उठाया कदम

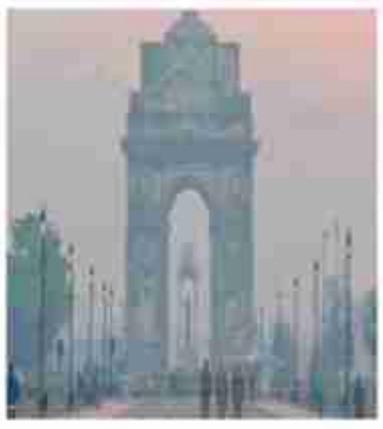

दिल्ली । राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने बड़ा निर्णय लिया है। उसने नई दिल्ली इलाके में वाहनों की गतिविधियों को कम करने और लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना करने की घोषणा की है। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण-दो के तहत उठाया गया है। एनडीएमसी के अनुसार, आयोग की उप-समिति की 19 अक्तूबर को हुई बैठक में पाया गया कि शाम सात बजे तक राजधानी का एक्यूआई 302 दर्ज किया गया था और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी की आशंका जताई गई थी। इसके बाद एनडीएमसी ने तत्काल प्रभाव से ग्रेप चरण-दो लागू करते हुए पार्किंग दरें बढ़ाने का निर्णय लिया। परिषद ने कहा है कि ग्रेप चरण-दो के निरस्त होने तक नई दिल्ली क्षेत्र में उसकी सभी ऑफ-स्ट्रीट और इनडोर पार्किंग स्थलों पर नई दरें लागू रहेंगी। अब चारपहिया वाहनों की पार्किंग फीस 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि दुपहिया वाहनों की दर 10 से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति घंटा की है। बसों के लिए शुल्क 150 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति घंटा और इनडोर पार्किंग में कारों के लिए 10 से 20 रुपये और दुपहिया के लिए पांच से 10 रुपये प्रति घंटा कर दिया गया है। एनडीएमसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थलों और मासिक पास धारकों के लिए यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी, क्योंकि सड़क किनारे की पार्किंग दरें पहले से ही अधिक हैं। एनडीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य वाहनों की संख्या घटाना और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर अंकुश लगाना है। पार्किंग शुल्क बढ़ने से लोगों को निजी वाहन घर में छोड़ने और सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस या ई-रिक्शा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। एनडीएमसी ने सभी पार्किंग संचालकों को नई दरों को तुरंत लागू करने और जनता को स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और ग्रेप चरण-दो के समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

तेज रफ्तार का कहर, राजेंद्र नगर में स्कूटी को टक्कर मारकर सड़क पर पलटी कार

नई दिल्ली । मध्य दिल्ली के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा पूसा रोड स्थित पिलर नंबर 96 के पास सुबह करीब 4 बजे हुआ। हादसे में एक स्कूटी और कार में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और कार पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक की पहचान और दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है। तेज रफ्तार और गलत साइड चलने को हादसे की वजह बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूटी सवार युवक गलत दिशा से आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर क्रेटा कार बेहद तेज और लापरवाही से चलाई जा रही थी। इसी टक्कर में दोनों स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और कार सड़क पर पलट गई। पहला घायल- लगभग 27 वर्षीय युवक, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। संदेह है कि वह रैपिडो ड्राइवर है।
उसे क्रेटा कार के ड्राइवर ने खुद आरएमएल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बाद में ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। दूसरा घायल ग्यानेंद्र प्रताप सिंह शेखावत (23 वर्ष), पुत्र राजेंद्र सिंह शेखावत, निवासी डी-656, मंदिर मार्ग। उसे पीसीआर वैन की मदद से लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि कार का चालक अंगद, पुत्र मनीदीप लाल कोठी, रोशनारा रोड का रहने वाला है।

साइबर ठगों ने एक ही दिन में पति-पत्नी के तीन खातों में लगाई सेंध, उड़ाए 10.70 लाख रुपये

नई दिल्ली । पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपती के तीन बैंक खातों से साइबर ठगों ने एक ही दिन में 10.70 लाख रुपये निकाल लिए। ठगी का शिकार हुए दंपती ने बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस को शक है कि वारदात में किसी करीबी व्यक्ति का हाथ भी हो सकता है। मामला पूर्वी जिले के साइबर थाने में दर्ज कर लिया गया है। 70 वर्षीय प्रियमवदा अस्थाना, जो सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, ने बताया कि वह घर पर थीं, तभी अचानक उनके मोबाइल पर लगातार बैंक ट्रांजैक्शन के मैसेज आने लगे। जब उन्होंने संदेश देखे तो पता चला कि खाते से 8.95 लाख रुपये निकल चुके हैं। उन्होंने तुरंत बैंक के कस्टमर केयर पर संपर्क किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच, उनके पति अनुराग अस्थाना, जो खुद भी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं, के मोबाइल पर भी वैसी ही मैसेज आने लगे। उनके दो खातों से क्रमशः 1.25 लाख और 49 हजार रुपये की निकासी हो चुकी थी। दंपती ने तुरंत बैंक शाखा को सूचित किया और अपने खाते बंद कराए। पीड़ितों का कहना है कि उनके पास किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले कोई ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) नहीं आया। उन्हें शक है कि बैंक सिस्टम के अंदर से किसी ने जानकारी लीक की है। उन्होंने बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। बैंक की सलाह पर दंपती ने 1930 हेल्पलाइन और साइबर थाना, पूर्वी जिला में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक पड़ताल में यह पाया गया है कि ठगी गई रकम कई खातों में ट्रांसफर की गई। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों के धारक कौन हैं और क्या इनका सीधा संबंध दंपती से है। पुलिस का कहना है कि संभावना है कि दंपती के किसी परिचित को बैंक की जानकारी थी।

चीन-अमेरिका की भिड़ंत में उलझा विश्व

आदित्य सिन्हा

इस महीने की शुरुआत में चीनी वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना से दुनिया में हड़कंप सा मचा। इसके जरिये अस्तित्व में आने वाला नियम विश्व व्यापार और उत्पादन के तौर-तरीके बदल सकता है। यह नियम रेयर अर्थ मैटेरियल कहे जाने तत्वों, परमानेंट मैग्नेट्स और संबंधित तकनीकों के निर्यात पर व्यापक नियंत्रण लगाता है। इस प्रविधान को समझें तो किसी भी कंपनी का उत्पाद जिसमें चीनी-प्रसंस्कृत रेयर अर्थ का 0.1 प्रतिशत हिस्सा भी शामिल है, उसे उसकी बिक्री या निर्यात से पहले बीजिंग की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सैन्य उपयोग के लिए निर्यात को तो सैद्धांतिक रूप से प्रतिबंधित ही कर दिया गया है, जबकि सेमीकंडक्टर्स और एआइ से संबंधित मामलों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सतही तौर पर तो चीन की यह पहल यह एक संकीर्ण व्यापार नियम जैसी प्रतीत हो सकती है, लेकिन वास्तव में यह वैश्विक आर्थिक शक्ति के संतुलन में किसी निर्णायक पड़ाव से कम नहीं है। रेयर अर्थ असल में 17 धातुओं का एक समूह है, जिनकी लड़ाकू विमान, पवन ऊर्जा टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन और चिकित्सा स्कैनर जैसे तमाम आधुनिक उत्पादों के निर्माण में अहम भूमिका होती है। मूल रूप से इनकी उपलब्धता उतनी दुर्लभ नहीं, जितना जटिल और महंगा इन्हें परिष्कृत कर उपयोग में लाने की पूरी प्रक्रिया है। यह पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंचाती है। तीन दशकों के दौरान चीन ने इन सामग्रियों के खनन, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए दुनिया का सर्वोत्तम तंत्र स्थापित कर लिया है। रेयर अर्थ के करीब 70 प्रतिशत खनन और 90 प्रतिशत परिष्करण में चीन की हिस्सेदारी से इस मोर्चे पर उसका दबदबा समझा सकता है। इस नए नियम के साथ चीन इस कोशिश में लगा है कि वह अपने औद्योगिक प्रभुत्व को रणनीतिक नियंत्रण के कानूनी उपकरण में बदल सके। पहली बार वह अमेरिकी नियमों के समान एक ऐसा ढांचा बना रहा है। अमेरिका भी अपने प्रभुत्व वाले उत्पादों की बिक्री एवं निर्यात के मामले में मनमाने प्रतिबंध करता आया है। बीजिंग ने इस पूरा रूप में और विस्तार दे दिया है कि अगर उसकी आपूर्ति वाले रेयर अर्थ का किसी तैयार उत्पाद में लेशमात्र भी उपयोग होता है तो उसके बारे में निर्णय का अधिकार उसका ही होगा। यह देशों की आर्थिक संप्रभुता को चुनौती देने वाला है। यह चीन की एक बड़ी रणनीतिक योजना है, जिसमें कानून, नियम और लाइसेंसिंग का उपयोग भू-राजनीतिक शक्ति के उपकरणों के रूप में किया जाता है। एक समय अमेरिका ने चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग के खिलाफ अतिरिक्त क्षेत्रीय व्यापार नियंत्रणों का उपयोग किया था। बीजिंग अब उन

तरीकों को दोहरा रहा है। प्रत्येक पक्ष अपने कार्यों को 'रक्षात्मक' के रूप में सही ठहराता है, लेकिन दोनों आर्थिक प्रतिशोध का ही प्रतीक है। चीन के इस कदम से कंपनियों को अब जटिल कागजी कार्रवाई, स्थानीय मध्यस्थों और स्वीकृति से जुड़ी शृंखलाओं के माध्यम से कोई तोड़ निकालना होगा। इसमें कई महीनों का समय भी लग सकता है। औपचारिक स्वीकृति के बिना आर्डर प्रभावित हो सकते हैं। मानो इतना ही पर्याप्त नहीं। चीन ने अपने पैकेजों को रेयर अर्थ से जुड़ी विदेशी परियोजनाओं में सहभागिता पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे तकनीकी ज्ञान का हस्तांतरण सीमित हो गया है। इससे डाटा, बैटरियों और औद्योगिक मानकों पर निगरानी भी बढ़ गई है। स्वाभाविक है कि कीमतों का परिदृश्य भी इस परिवर्तन से प्रभावित होगा। इलेक्ट्रिक मोटर्स में उपयोग होने वाले प्रमुख रेयर अर्थ नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम की कीमतें बढ़ गई हैं। निर्माता गैर-चीनी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी और आस्ट्रेलियाई विकल्पों की निर्बाध आपूर्ति में अभी कई साल लग सकते हैं। परिणामस्वरूप स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। इसके पीछे मांग में कमी नहीं, बल्कि कच्चे माल की बाधाएं अधिक जिम्मेदार होंगी। ऐसा नहीं कि इसमें चीन के लिए कोई जोखिम नहीं है। उसके ऐसे कड़े नियंत्रण से वैश्विक खरीदार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत में विकल्प खोजने में जुटेंगे। याद रहे कि कड़ी लाइसेंसिंग खुद अपने उद्योगों में नवाचार को हतोत्साहित करती है। वर्तमान परिस्थितियां दुनिया को दो अलग प्रणालियों में विभाजित कर रही है। एक के केंद्र में चीन है, जो खनन, परिष्करण और उत्पादन को एक ही राज्य-नियंत्रित ढांचे में एकीकृत करता है। दूसरी प्रणाली के केंद्र में अमेरिका है, जहां सब्सिडी और औद्योगिक नीति के माध्यम से क्षमताओं को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह दोहराव लचीलापन तो बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें लागत बढ़ोतरी का पहलू भी शामिल है। इतना ही नहीं, इससे स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला विविधीकरण की दिशा में हो रही प्रगति भी धीमी पड़ सकती है। अन्य देशों के लिए इसमें जोखिम और अवसर दोनों ही विद्यमान हैं। ये देश वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में नए निवेश को आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिस्पर्धी कानूनी प्रणालियों और राजनीतिक दबावों के भंवर में कोई कारगर युक्ति निकालनी होगी। चीन का दृष्टिकोण सुनियोजित प्रतीत होने के बावजूद असमर्थ है। वहीं, अमेरिकी कार्रवाइयों में पारदर्शिता की झलक के साथ ही उसकी प्रकृति अस्थिर एवं अनिश्चित है। दोनों ही देश अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक विकल्पों को हथियार बनाने में लगे हैं, लेकिन शायद ही किसी को उनके दीर्घकालिक परिणामों की कोई परवाह है। बीजिंग और वाशिंगटन दोनों को यह समझना होगा कि बेलगाम प्रभुत्व की स्थिति बहुत नाजुक होती है। यह अपने ही सहयोगियों को दूर करके अंततः स्वयं को ही कमजोर करती है। स्मरण रहे कि शक्ति केवल संसाधनों के स्वामित्व में नहीं, बल्कि उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से संचालित करने की क्षमता में निहित है। कानून और प्रभाव के इस नए युग में वही राष्ट्र इस सदी की दिशा निर्धारित करेंगे, जो संयम, पारदर्शिता और समन्वय का परिचय देंगे।

सम्पादकीय...

घरेलू खपत बन रही है बड़ा सहारा

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और व्यापार तनाव के चलते वैश्विक वृद्धि दर धीमी रही, फिर भी मजबूत घरेलू खपत के दम पर भारत 6.6 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करते हुए दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक विकास दर की संभावनाएं रखता है। भारत की विकास दर चीन से भी अधिक अनुमानित है। इसी तरह एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स की नई रिपोर्ट में कहा गया कि इस समय वैश्विक व्यापार की चुनौतियों और ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ के चलते भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर से मार्च के बीच तेज घरेलू खपत और सरकार का पूंजीगत व्यय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत सहारा बनता हुआ दिख रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि दीवाली पर बिक्री रिकार्ड ऊंचाई पर रही है। ई-कामर्स ने दमदार उछाल दर्ज की। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी के कारण जीएसटी बचत उत्सव का परिदृश्य दिखाई दिया। महंगाई में कमी और जीएसटी की दरें घटना देश के बाजारों की तेज बढ़त के लिए एक बड़ा आधार है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 के दौरान खुदरा महंगाई घटकर 1.54 प्रतिशत रह गई। इससे पिछले महीने यह 2.07 प्रतिशत थी। यही खुदरा महंगाई दर सितंबर 2024 में 5.49 प्रतिशत थी। सितंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर आठ साल में सबसे कम रही और यह आरबीआइ के अनुमानित लक्ष्य के भी निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ-साथ सितंबर में थोक महंगाई दर भी तेजी से घटकर 0.13 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। महंगाई दर घटने के साथ 22 सितंबर से जीएसटी सुधारों के लागू होने से इस बार दीवाली के त्योहारी बाजार में खरीदारी को पंख लगे। जीएसटी दरों के साथ-साथ आयकर में कटौती से लोगों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत प्राप्त हुई है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर 2025 में भारत का फाइनेंशियल वेलबीइंग इंडेक्स (एफडब्ल्यूबीआइ) 110.3 तक पहुंच गया है, जो वैश्विक औसत 103.6 से ज्यादा है। इसके साथ ही उपभोक्ता विश्वास भी पिछले साल से आठ अंक बढ़ा है, जो 2022 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। यह भी उल्लेखनीय है कि फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक जहां वर्ष 2023 में दीवाली के त्योहारी बाजार में 3.75 लाख करोड़ रुपये और वर्ष 2024 में 4.25 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी हुई थी, वहीं इस बार त्योहारी सीजन के तहत खरीदारी पांच लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने और अमेरिका में डालर की वैल्यू घटने से इस साल त्योहारी सीजन में चांदी और सोने के भाव भी रिकार्ड स्तर पर रहे और शेयर बाजार का ग्राफ भी बढ़ा। विदेशी मुद्रा भंडार भी 700 अरब डालर के स्तर पर है। इस सबके परिणामस्वरूप इस समय औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर तक मांग का बढ़ता हुआ नया अध्याय दिखाई दे रहा है। मांग और उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू खपत के साथ-साथ कुछ और आर्थिक अनुकूलताएं भी उभरती दिख रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूस और चीन के साथ आर्थिक-वैश्विक कूटनीति और नए निर्यात बाजारों में आगे बढ़ने की जो रणनीति अपनाई, वह कारगर होती दिखाई दे रही है। इस नीति से ट्रंप टैरिफ के बीच पिछले अगस्त और सितंबर माह में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों में भारत के निर्यात बढ़े हैं। हाल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को ट्रंप के ऊंचे टैरिफ से हो रहे नुकसान की पूर्ति के लिए भारत के साथ रूस के व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। इस सबके साथ विभिन्न देशों के साथ तेजी से आकार लेते हुए दिखाई दे रहे भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) निर्यात के मद्देनजर मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इस समय भारत मजबूत घरेलू खपत और नई वैश्विक आर्थिक अनुकूलताओं की उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने के लिए उसे कई अहम बातों पर ध्यान देना होगा। जीएसटी के बाद अब देश को अगली पीढ़ी के सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। इन सुधारों के तहत जीवन सहजता, कारोबार सुगमता, बुनियादी ढांचा सुधार, प्रशासन को सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने संबंधी सुधार शामिल हैं। देश को अब श्रम, बीमा, परिवहन, दूरसंचार, बिजली, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज सुधारों की डगर पर आगे बढ़ना होगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फार लोकल के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए पूरे देश में और अधिक लोग स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों के उपयोग को जीवन का मूलमंत्र बनाएंगे। इससे देश मजबूत घरेलू खपत के साथ आत्मनिर्भरता की डगर पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच लगातार आगे बढ़ रहे भारत में घरेलू खपत तथा प्रति व्यक्ति आय में और तेजी से वृद्धि होगी और इससे अर्थव्यवस्था के साथ आम आदमी की मुस्कुराहट भी बढ़ती हुई दिखाई देगी।

मध्य एशिया में भारत की पकड़ ढीली हुई, खाली करना पड़ा ताजिकिस्तान में स्थित एयरबेस

नीरज कुमार दुबे

भारत अब ताजिकिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आयनी एयरबेस का संचालन नहीं करता, जिसे उसने 2002 से विकसित और संयुक्त रूप से संचालित किया था। यह जानकारी हाल ही में सार्वजनिक हुई है, किंतु सूत्रों के अनुसार भारत ने 2022 में ही इस बेस से पूरी तरह वापसी कर ली थी।

हम आपको बता दें कि भारत और ताजिकिस्तान के बीच यह सहयोग एक लीज अनुबंध पर आधारित था, जिसकी अवधि 2021 में समाप्त हो गयी थी। ताजिकिस्तान ने संभवतः रूस और चीन के दबाव के कारण इसे आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद भारत ने अपने सैन्य कर्मियों और उपकरणों को वहां से हटा लिया। हालांकि वहाँ भारत की कोई स्थायी वायुसेना तैनाती नहीं थी, लेकिन दो-तीन हेलीकॉप्टर जो भारत ने ताजिकिस्तान को भेंट किए थे, वह भारतीय वायुसेना के कर्मियों द्वारा मानवतावादी और राहत अभियानों में संचालित किए जाते थे। कभी-कभी Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की अस्थायी तैनाती भी वहां की गई थी। हम आपको बता दें कि आयनी एयरबेस (जिसे गिस्सार मिलिट्री एयरोड्रोम-GMA भी कहा जाता है) ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से पश्चिम में स्थित है। इसे भारत ने लगभग दो दशक तक विकसित किया और इसके विस्तार पर लगभग 100 मिलियन डॉलर खर्च किए। यह वही ठिकाना था जहाँ से भारत ने 2001 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अपने नागरिकों की निकासी में भी सहायता ली थी। भारत ने इस बेस को अपनी सामरिक पहुँच के रूप में उपयोग किया था, विशेषकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दिशा में। देखा जाये तो भारत की आयनी एयरबेस से वापसी, सिर्फ़ एक कूटनीतिक या प्रशासनिक घटना नहीं है, यह दक्षिण और मध्य एशिया की भू-राजनीतिक संरचना में एक गहरा परिवर्तन है। यह निर्णय ऐसे समय सामने आया है जब मध्य एशिया, विशेष रूप से ताजिकिस्तान, रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव में है और भारत की वहाँ की सामरिक पकड़ कमजोर होती

जा रही है। हम आपको बता दें कि आयनी एयरबेस भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का केंद्रबिंदु था। 2001 में अफगानिस्तान संकट के बाद जब पाकिस्तान के रास्ते भारत की पहुँच अवरुद्ध थी, तब ताजिकिस्तान में यह एयरबेस भारत की एकमात्र ऐसी संपत्ति थी जिससे वह अफगान मामलों और उत्तरी दिशा के रणनीतिक परिदृश्य में सक्रिय रह सकता था। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल जैसे रणनीतिक मस्तिष्कों ने इसे भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी का हिस्सा बनाया था। इसके 3,200 मीटर लंबे रनवे ने भारतीय वायुसेना को यह क्षमता दी थी कि वह न केवल अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान के उत्तरी ठिकानों (जैसे पेशावर) तक अपनी पहुंच बना सके। हम आपको बता दें कि ताजिकिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक संरचना रूस पर काफी हद तक निर्भर है। रूस के 201वें सैन्य डिवीजन की वहाँ स्थायी तैनाती है और चीन ने भी ताजिकिस्तान में सीमा-पुलिस और खुफिया ठिकानों के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में भारत का एक स्वतंत्र सैन्य ठिकाना, रूस-चीन दोनों के लिए सामरिक असुविधा बन गया था। रूस नहीं चाहता था कि भारत या कोई अन्य गैर-क्षेत्रीय शक्ति मध्य एशिया में स्वतंत्र सैन्य उपस्थिति बनाए रखे। दूसरी ओर, चीन ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के वाखान कॉरिडोर को अपनी पश्चिमी सुरक्षा-पट्टी के रूप में देखता है। इस क्षेत्र में भारतीय गतिविधि, उसे स्ट्रैटेजिक इनक्लोजमेंट का आभास देती थी। देखा जाये तो आयनी एयरबेस से भारत की वापसी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अब भारत की «नॉर्थ-वेस्टर्न डिफेंस एक्सटेंशन» पूरी तरह समाप्त हो गई है। पाकिस्तान के साथ संभावित दो-फ्रंट स्थिति (पूर्वी और पश्चिमी मोर्चा) में भारत को जो सामरिक बढ़त मिल सकती थी, वह अब खो चुकी है। अब भारत को वायुसेना को कश्मीर और लद्दाख के बेसों से ही पश्चिमी अभियानों की योजना बनानी होगी, जबकि ताजिकिस्तान से ऑपरेशन की स्थिति में पाकिस्तान को पश्चिम से दबाव झेलना पड़ता। आयनी एयरबेस से वापसी यह भी दर्शाती है कि भारत की मध्य एशिया में भू-आर्थिक पहुंच सीमित है। चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के बावजूद भारत ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान तक कोई सुरक्षित लॉजिस्टिक चैनल स्थापित नहीं कर सका। इस विफलता ने भारत को क्षेत्रीय गठबंधनों में एक सीमित भागीदार बना दिया है, जबकि चीन अपने Belt and Road Initiative के जरिए वहाँ स्थायी प्रभाव बना रहा है। आगे का रास्ता क्या हो, यदि इसको देखें तो सबसे पहले तो भारत को इस घटना को पराजय के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्रचना के अवसर के रूप में देखना चाहिए। भारत ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ संयुक्त प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और मानवीय परियोजनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रख सकता है। इंटेलिजेंस साझेदारी और काउंटर-टेररिज्म सहयोग के नए प्रारूप भारत को पुनः प्रभावी भूमिका दे सकते हैं। साथ ही, ईरान के माध्यम से वैकल्पिक पहुँच मार्ग (जैसे चाबहार से मध्य एशिया तक कॉरिडोर) को त्वरित गति देनी होगी। बहरहाल, आयनी एयरबेस का खोना भारत की सामरिक सीमाओं की याद दिलाता है कि केवल निवेश और तकनीक से भू-राजनीति नहीं चलती; इसके लिए स्थायी गठबंधन, राजनीतिक प्रभाव और लॉजिस्टिक क्षमता आवश्यक है। भारत यदि मध्य एशिया में अपनी जगह पुनः बनाना चाहता है, तो उसे केवल सैन्य दृष्टिकोण नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक त्रिकोणीय रणनीति अपनानी होगी।

राफेल से उड़ान भरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिर्फ इतिहास नहीं रचा है बल्कि महिलाओं और आदिवासी समाज को गौरव से भर दिया है

नीरज कुमार दुबे

29 अक्टूबर 2025 का दिन भारतीय वायुसेना और पूरे राष्ट्र के लिए एक विशेष दिन के रूप में याद किया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। यह वही अंबाला एयरबेस है, जहां फ्रांस से आए राफेल विमानों की पहली खेप उतरी थी। लगभग 30 मिनट तक चली इस उड़ान में राष्ट्रपति ने करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की, जो 15,000 फीट की ऊंचाई और लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर संपन्न हुई। विमान को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गहाणी ने संचालित किया।

न भरना मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है। इससे मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमता पर गर्व की नई अनुभूति हुई है। इस प्रकार, यह केवल एक प्रतिकात्मक उड़ान नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, सामरिक शक्ति और नागरिक गर्व का सशक्त संदेश थी। हम आपको बता दें कि राफेल भारत की सामरिक शक्ति का आधुनिक प्रतीक है। 4.5 पीढ़ी का यह मल्टीरोल लड़ाकू विमान वायुसेना की परिचालन क्षमता को कई गुना बढ़ाता है। राष्ट्रपति का राफेल में उड़ान भरना एक औपचारिक या औपचारिकता-भर कदम नहीं, बल्कि यह संकेत है कि राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति देश की रक्षा तैयारियों पर पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रहा है। भारत की राष्ट्रपति, जो संवैधानिक रूप से सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, उनका ऐसे लड़ाकू विमानों में उड़ान भरना सैन्य बलों के मनोबल को बढ़ाता है। साथ ही यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने रक्षात्मक ढाँचे को लेकर न केवल सजग है, बल्कि उस पर गर्व भी करता है। राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान में राष्ट्रपति की उपस्थिति से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी यह संदेश जाता है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और वायु सामर्थ्य के मामले में किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं है। इसके अलावा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व स्वयं में संघर्ष, सादगी और उत्कर्ष का प्रतीक है। ओडिशा के एक छोटे आदिवासी परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुँचना अपने आप में प्रेरक कथा है। जब वह सुखोई-30 एमकेआई (2023) के बाद अब राफेल जैसे उन्नत तकनीकी लड़ाकू विमान में उड़ान भरती हैं, तो यह दृश्य करोड़ों महिलाओं और आदिवासी युवाओं के लिए आत्मबल और आत्मविश्वास का स्रोत बनता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह संदेश अत्यंत सशक्त है कि राष्ट्र की सुरक्षा, तकनीकी शक्ति और निर्णय क्षमता के क्षेत्र में अब लैंगिक भेद की दीवारें टूट चुकी हैं। एक महिला राष्ट्रपति का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान में उड़ान भरना इस बात का प्रमाण है कि महिलाएँ अब केवल 'संवेदनशीलता' का प्रतीक नहीं, बल्कि 'साहस' और 'संकल्प' की मिसाल भी हैं। आदिवासी समाज के लिए यह गौरव का क्षण है। दशकों से समाज के हाशिए पर रहे तबकों के लिए यह दृश्य 'राष्ट्रीय मुख्यधारा में समान भागीदारी' की अभिव्यक्ति है। जब देश की सर्वोच्च नेता आदिवासी समुदाय से आती हैं और आधुनिकतम सैन्य तकनीक के बीच आत्मविश्वास से भरी दिखाई देती हैं, तो यह सामाजिक मनोविज्ञान को गहराई से प्रभावित करता है। इससे यह संदेश जाता है कि अब कोई भी पृष्ठभूमि प्रगति और नेतृत्व की राह में बाधा नहीं बन सकती। इसके अलावा, राष्ट्रपति का यह कदम केवल सैन्य प्रतीक नहीं, बल्कि एक राष्ट्रनैतिक वक्तव्य भी है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति के मार्ग पर विश्वास का उद्घोष है।

नारी शक्ति और जनजातीय गौरव को केंद्र में रखकर यह दृश्य भारत के बदलते समाज की नई कहानी कहता है– जहाँ संवैधानिक गरिमा, तकनीकी श्रेष्ठता और सामाजिक समावेशन का संगम दिखाई देता है। साथ ही, भारतीय वायुसेना के लिए यह अवसर आत्मगौरव का भी है। एक राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का राफेल में उड़ान भरना वायुसेना के प्रशिक्षण, अनुशासन और तकनीकी दक्षता पर सर्वोच्च विश्वास का प्रमाण है। यह संदेश सैन्य परंपरा की निरंतरता और आधुनिकता के मेल का है– जहाँ संवैधानिक संस्थाएँ और सशस्त्र बल एकजुट होकर राष्ट्र सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू का यह कदम भारत के उन तमाम युवाओं को भी प्रेरित करेगा जो रक्षा सेवाओं में योगदान देने का सपना देखते हैं। जब देश की प्रथम नागरिक स्वयं युद्धक विमान में उड़ान भरती हैं, तो यह युवाओं के भीतर 'कर्तव्य', 'साहस' और 'सेवा' के आदर्श को पुनः जीवंत करता है।

बहरहाल, द्रौपदी मुर्मू का राफेल में उड़ान भरना मात्र एक प्रतीकात्मक घटना नहीं, बल्कि एक युगबोध है। यह उस भारत की कहानी है जो अपनी परंपरा को सम्मान देता है, आधुनिकता को अपनाता है और समावेशन को अपनी शक्ति बनाता है।

न्याय में देरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई चिंता

आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोप तय होने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए इस संदर्भ में देश भर के लिए दिशानिर्देश तय करने के संकेत दिए। इसे लेकर वह गंभीर है, इसका पता इससे चलता है कि उसने अटार्नी जनरल एवं सालिसिटर जनरल से मदद मांगी और एक वरिष्ठ वकील को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त भी कर दी। बहुत संभव है कि वह आरोप तय करने के मामले में कोई दिशानिर्देश भी सुना दे, लेकिन क्या इतने मात्र से समस्या का समाधान हो जाएगा? उसे इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि आरोप तय होने में देरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 251(बी) के तहत दिए गए इस स्पष्ट प्रविधान के बावजूद हो रही है कि जिन मामलों की सुनवाई केवल सत्र न्यायालय द्वारा की जानी है, उनमें पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर ऐसा कर दिया जाना चाहिए। आखिर जब आरोप तय करने की समयसीमा को लेकर पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, तब फिर एक और व्यवस्था देने यानी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश बनाने से समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? अच्छा होगा कि वह दिशानिर्देश बनाने के पहले उन कारणों का निवारण करे, जिनके चलते आरोप तय होने में देर होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसकी आशंका है कि उसके दिशानिर्देशों के बाद आरोप तो एक समयसीमा में तय हो जाएं, पर मुकदमों के निपटारे में तब भी विलंब होता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय होने में देरी का संज्ञान तब लिया, जब उसके समक्ष एक ऐसा प्रकरण आया, जिसमें आरोपित के एक साल से हिरासत में होने के बाद भी उसके मामले में आरोप तय नहीं किए जा सके हैं। इस प्रकरण पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जिला अदालतों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि सीधे संपूर्ण भारत के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा। उसे ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन क्या जिला अदालतों से यह जानना आवश्यक नहीं कि आरोप तय होने में विलंब क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट को उन कारणों से भी परिचित होने की आवश्यकता है, जिनके चलते पहले आरोप पत्र दाखिल होने में देरी होती है और फिर आरोप तय होने में। उसे इससे भी अवगत होना चाहिए कि ये दोनों काम हो जाने पर भी मुकदमों का निपटारा समय पर नहीं होता। ऐसा केवल निचली अदालतों ही नहीं, बल्कि उच्चतर अदालतों में भी होता है। ऐसा जिन कारणों से होता है, उनमें से एक न्यायाधीशों और वकीलों की कार्यप्रणाली भी है। तारीख पर तारीख के सिलसिले को कायम करने वाली इसी कार्यप्रणाली के चलते समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने करन आफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/0882)

दिल्ली में इस महीने 12 मुठभेड़...15 से अधिक बदमाश गिरफ्तार, सात शातिर ढेर; कई वांछित दबोचे

दिल्ली । दिल्ली में इस महीने 12 से अधिक मुठभेड़ें हुई हैं। इनमें 15 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बिहार में सक्रिय गिरोह के चार सदस्यों समेत सात बदमाश मारे गए। इन अभियानों के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से कई पुलिसकर्मियों की जान बच गई। दिल्ली पुलिस की एक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि लगातार जारी यह अभियान संगठित अपराध नेटवर्क और राजधानी व आसपास के राज्यों में सक्रिय बदमाशों के खिलाफ पुलिस की रणनीति को दर्शाता है। पुलिस ने दावा किया कि दो अक्टूबर को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की सुपारी लेकर आए रोहित गोदारा उर्फ गोल्डी बराड़ उर्फ वीरेंद्र चारण गिरोह के दो सदस्यों को जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया।आरोपियों की पहचान हरियाणा के राहुल और साहिल के रूप में हुई। पुलिस का दावा है कि वह विदेश में मौजूद गैंगस्टर रोहित गोदारा के निर्देश पर काम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि यमुनानगर में तीन लोगों की हत्या के मामले में आरोपी राहुल मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने कहा कि अगले दिन तीन अक्टूबर को इसी गिरोह से जुड़े दो और बदमाशों को कापसहेड़ा में मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया, जिनकी पहचान राजस्थान के आकाश राजपूत और महिपाल के रूप में हुई।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों के खिलाफ तीन राज्यों में रंगदारी और अपहरण के कई मामले दर्ज थे। उन्होंने बताया कि बीस हजार रुपये के इनामी बदमाश राजपूत को पैर में गोली लगने के बाद पकड़ लिया

दिल्ली में बरसीं गोलियां, दुष्कर्म मामले का वांछित अपराधी गुड्डू गिरफ्तार

गया। पुलिस ने बताया कि दोनों दलेर कोटिया गैंग के साथ काम करते थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमजा ने अपने दोस्त आदिल की हत्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, उसने पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने के बाद वह पकड़ा गया। पुलिस ने कहा कि दस अक्टूबर को नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक और मुठभेड़ में अफताब आलम उर्फ अट्टी नाम का अपराधी घायल हुआ। आरोपी ने पुलिस पर दो बार गोली चलाई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में घायल होने के बाद पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि 12 दिन बाद, 22 अक्टूबर को द्वारका में मुठभेड़ के बाद रितिक उर्फ झांसर नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया गया। रितिक उत्तम नगर में हत्या के एक मामले में वांछित था। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में मंगलवार आधी रात को एक बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई।

बदमाश ने पुलिस पर दो राउंड गोलियां दाग दीं। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में चलाई एक गोली बदमाश की टांग में लगी। बाद में उसे काबू कर लिया गया। आरोपी इमरान उर्फ काला (21) को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम ने उसके पास से एक पिस्टल, दो कारतूस व चोरी की एक बाइक बरामद की है। आरोपी के खिलाफ वेलकम थाने में कई आपराधिक मामले हैं। उत्तर-पूर्वी जिला के पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि मंगलवार रात को जिले का स्पेशल स्टाफ न्यू उस्मानपुर इलाके में गश्त पर था। इस बीच जौरो पुश्ता, बिजली घर के नजदीक टीम ने बगैर नंबर प्लेट की बाइक पर एक युवक को आते हुए देखा। युवक को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। पुलिस टीम को देखते ही आरोपी ने एकदम पिस्टल निकालकर टीम पर गोली चला दी। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी। पुलिस ने दोबारा आरोपी से सरेंडर करने की अपील की। इसके बाद आरोपी ने दोबारा टीम पर फायर कर दिया। गोली स्पेशल स्टाफ में तैनात सिपाही परमजीत की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। फौरन पुलिस ने दो राउंड गोली चलाई। एक गोली बदमाश की टांग में लगी। फौरन उसे काबू कर लिया गया।

रेखा सरकार की पहली बड़ी परीक्षा: एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी ने सांसदों को रखा बाहर, मंत्रियों-विधायकों पर भरोसा

नई दिल्ली । एमसीडी के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने सांसदों को औपचारिक जिम्मेदारियों से दूर रखते हुए सारा भरोसा मंत्रियों और विधायकों पर जताया है। संगठन ने साफ संदेश दिया है कि उपचुनाव रेखा गुप्ता सरकार की पहली बड़ी परीक्षा है और इसे पूरी गंभीरता से लड़ा जाएगा। भाजपा ने दिल्ली सरकार के सभी छह मंत्रियों को दो-दो वार्डों का प्रभारी (इंचार्ज) बनाया है। विधायकों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को एक-एक वार्ड का संयोजक नियुक्त किया गया है। इन प्रभारी और संयोजकों को बूथ स्तर तक की निगरानी, मतदाता संपर्क और प्रचार की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि भाजपा चाहती है कि मंत्री और विधायक सीधे जनता के बीच जाकर सरकार के कामकाज को बताएं। सांसदों को किसी वार्ड की औपचारिक जिम्मेदारी नहीं दी गई है, हालांकि सांसदों पर अपने संसदीय क्षेत्र के वार्डों में प्रचार और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की जिम्मेदारी रहेगी। महिला मोर्चा छोड़कर प्रत्येक मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी को एक-एक वार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे कहा गया है कि वे अपने मोर्चे से जुड़े वर्ग युवा, अनुसूचित जाति, व्यापारी आदि के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएं। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर भी तेजी से काम हो रहा है। भाजपा ने तय किया है कि प्रत्याशी के नाम जिला अध्यक्ष, स्थानीय विधायक और संबंधित सांसद की राय से तय होंगे और उन्हें तीन नवंबर तक प्रदेश नेतृत्व को भेजना होगा। नामांकन प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो जाएगी, इसलिए पार्टी चाहती है कि उम्मीदवार समय रहते मैदान में उतरें और प्रचार को गति दें। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और संगठन महामंत्री पवन राणा रणनीति तय कर रहे हैं। उन्होंने सभी प्रभारी और संयोजकों को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ता बैठकों को नियमित रूप से संचालित करें। भाजपा चाहती है कि 30 नवंबर को होने वाले इन उपचुनावों में अधिकतम सीटें जीतकर यह साबित करे कि दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज पर भरोसा रखती है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बार पार्टी स्थानीय चेहरों पर दांव लगाएगी। वह वार्ड स्तर पर सक्रिय और जनता से गहरा जुड़ाव रखने वाले नेताओं को टिकट देगी। पार्टी का मानना है कि यह उपचुनाव केवल चेहरों का नहीं बल्कि भाजपा की ग्राउंड नेटवर्क क्षमता और जनता से जुड़ाव की परीक्षा है।

मां-बाप बनने की ख्वाहिश ने बना दिया किडनैपर: नौकरानी और नाबालिगों संग मिल बनाया प्लान

नई दिल्ली । तिलक नगर इलाके में निः संतान दंपती ने एक घरेलू सहायिका और नाबालिगों की मदद से 27 दिन के एक मासूम बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ कर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है। पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर ने बताया कि तिलक नगर थाना पुलिस को 27 दिन के बच्चे के अगवा होने की शिकायत उसके परिजनों ने दी थी। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल और आरोपियों के भागने की दिशा में करीब दो सौ कैमरे की जांच की। जिसमें पता चला कि स्कूटी सवार दो लोगों ने बच्चे को अगवा किया है। जांच में पता चला कि स्कूटी नारायणा से चोरी हुई थी। चोरी करने वाला विकास एक अन्य मामले में जेल में बंद है। उसके जरिए पता चला कि उसने स्कूटी अनिल को सौंप दी थी, जिसने स्कूटी को एक नाबालिग को दे दी थी। पुलिस ने नाबालिग को पकड़ कर पूछताछ की, जिसमें अपहरण का खुलासा हुआ।

पुलिस ने उसके बाद निःसंतान दंपती उत्तम नगर निवासी शुभ करण, संयोगिता, घरेलू सहायिका माया और एक अन्य नाबालिग को पकड़ लिया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि कीर्ति नगर में काम करने वाली माया की पड़ोस में रहने वाली निःसंतान दंपती से दोस्ती हो गई। उसे जब पता चला कि शादी के कई वर्षों बाद भी दंपती निःसंतान हैं, तो उसने उनके साथ मिलकर बच्चे को अगवा करने की साजिश रची। उन लोगों ने सुभाष नगर स्थित पैसिफिक मॉल के पास सड़क किनारे रहने वाली एक महिला के नवजात शिशु को अगवा करने के लिए नाबालिगों को तैयार किया और उन्हें 20 हजार देने का वादा किया। उसके बाद दोनों नाबालिगों ने बच्चे को अगवा कर उसे माया को सौंप दिया। इनके कब्जे से पुलिस ने अपहृत शिशु को छुड़ा कर उसे माता-पिता को सौंप दिया है।

राजस्थान में चक्रवाती बारिश से बढ़ी ठंड, 13 जिलों में यलो अलर्ट; सिरोही सबसे ठंडा शहर

जयपुर । अरब सागर में बने चक्रवात का असर अब भी राजस्थान में जारी है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। इसके बाद आज गुरुवार तड़के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर सहित कई जिलों में तेज बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। तापमान में औसतन 8-10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भी राज्य के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी इलाकों में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। सिरोही इस सीजन का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और अजमेर में भी दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा। बारिश के असर से खेती में भी नुकसान देखने को मिल रहा है।

टोंक जिले के दूनी क्षेत्र में तेज बारिश से सरसों की फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह चक्रवाती प्रभाव 30 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा। 31 अक्टूबर को कुछ शहरों में आंशिक बादल और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। 29 अक्टूबर को राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में ठंडक का असर और बढ़ गया। दिनभर बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान की स्थिति इस प्रकार रही। अजमेर में अधिकतम तापमान 24.3 और न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि भीलवाड़ा में पारा 24.2 और 18 डिग्री दर्ज हुआ। अलवर में अधिकतम 28.8 और न्यूनतम 17.5 डिग्री, जयपुर में 26.7 और 18.8, पिलानी में 29.5 और 16.4, सीकर में 29 और 16 डिग्री रहा। कोटा में तापमान 23.6 और 18.6 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 24.8 और 18, उदयपुर में 22.2 और 18.1, बाड़मेर में 30.6 और 20.8, जबकि जैसलमेर में अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 18.8 डिग्री दर्ज हुआ। जोधपुर में 28.4 और 20, बीकानेर में 30.8 और 19.8, चूरू में 30.2 और 18.8, गंगानगर में 32.5 और 17.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।नागौर में 29.9 और 18.6, डूंगरपुर में 25.8 और 20.2, हनुमानगढ़ में 31.9 और 19.3, जालौर में 26.8 और 21.4, सिरोही में 19.4 और 14.7, करौली में 27.1 और 19.1, दौसा में 27.2 और 18.7, प्रतापगढ़ में 24.5 और 19.8, झुंझुनूं में 29.1 और 18.4, जबकि पाली में अधिकतम 25.4 और न्यूनतम 18.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

नियमों के विपरीत आवास आवंटन पर जीएडी सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

शिमला । हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों के विपरीत सरकारी आवास आवंटन पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सरकारी आवास सामान्य पूल के आवंटन को भी रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने जुर्माने की राशि को मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने पाया कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने आवास आवंटन करते समय कानून की प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया। अदालत ने 5 जनवरी, 2024 और 16 मार्च, 2024 के आवास आवंटन पत्रों को रद्द कर दिया है। अदालत ने उस आवंटन को रद्द कर दिया, जिसके तहत एक ड्राइवर को आउट ऑफ टर्न सरकारी आवास आवंटित किया गया था, जबकि अन्य कर्मचारियों के पुराने आवेदन विचाराधीन थे। अदालत ने अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर यान्त्रिकाकर्ता और प्रतिवादी ड्राइवर के आवेदनों पर हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास (सामान्य पूल) आवंटन

नियम 1994 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के आवंटन नियमों और सुमित कुमार के फैसले के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पाया कि यह आवंटन जल्दबाजी में किया गया। यह हिमाचल प्रदेश आवंटन ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंसेस जनरल पूल रूल्स 1994 के नियम 8 (7) का उल्लंघन था। नियम के अनुसार आउट ऑफ टर्न आवंटन की शक्ति हाउस अलॉटमेंट कमेटी में निहित है न कि प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन में है। अदालत ने इस कार्रवाई को अनुचित, घोर अनियमितता वाला और अवैध माना है।

सफीदों से बीजेपी विधायक के बयान पर बचते नजर आए कृषि मंत्री

झज्जर । सफीदों विधानसभा से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के सिस्टम पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बचते नजर आए। वह बुधवार को जिला परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि रामकुमार गौतम हमारी पार्टी के सीनियर विधायक हैं और उनको बहुत अनुभव है। पार्टी के अंदर उनका बहुत सम्मान है। बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि बिहार में एक तरफ चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और एनडीए गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। चाहे किसानों के गन्ने का एमएसपी बढ़ाने की बात हो या धान व गेहूं आदि फसलों की एमएसपी पर खरीद हो, हर कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन को लेकर सरकार सजगता के साथ कार्य कर रही है। फसल अवशेष प्रबंधन किसान चाव से अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मान देने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार जन समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। जन समस्याओं का प्रभावी समाधान करते हुए नागरिकों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 11 शिकायतों का दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मौके पर ही समाधान कर दिया गया जबकि 3 शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा गया।

सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ाया, नई दर एक जुलाई से लागू

जम्मू जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर और पेंशनधारकों को मूल पेंशन पर 55 फीसदी की जगह 58 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह संशोधित दरें एक जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की संख्या 5.10 लाख के करीब है और पेंशनधारकों की संख्या लगभग 2.40 लाख है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2025 तक के एरियर का नकद भुगतान अक्तूबर महीने में किया जाएगा। अक्तूबर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नियमित वेतन और पेंशन में जोड़ा जाएगा। यह आदेश सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और उसी के अनुरूप पेंशन पा रहे सेवानिवृत्त कर्मियों पर लागू होगा।

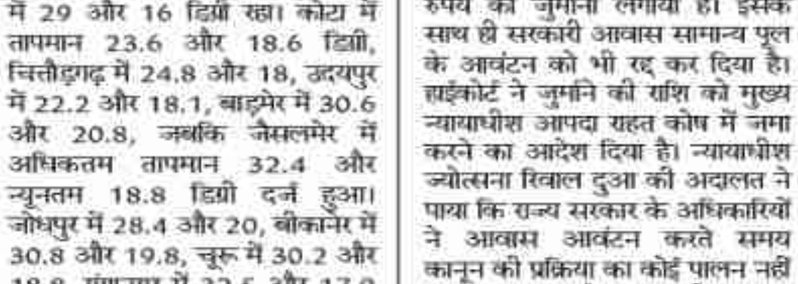

विभाग ने स्पष्ट किया है कि मूल वेतन का अर्थ सातवें वेतन आयोग की वेतन संरचना में निर्धारित स्तर के अनुसार मिलने वाला वेतन है, जिसमें विशेष वेतन जैसी कोई अतिरिक्त राशि शामिल नहीं होगी। यह फैसला 15 अक्तूबर, 2025 को हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में लिया गया था। सरकार के अनुसार महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी महंगाई के दबाव को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देने के उद्देश्य से की गई है। छठे वेतन आयोग वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए भी आदेश जारी वित्त विभाग ने उन कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए भी अलग आदेश जारी किया है जो अब भी छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आदेश के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अब मूल वेतन पर 252 फीसदी की जगह 257 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं, पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी मूल पेंशन पर 257 फीसदी डीए मिलेगा। यह संशोधित दरें भी एक जुलाई 2025 से लागू होंगी और जुलाई से सितंबर तक का एरियर अक्तूबर महीने में नकद रूप में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में आने की संभावना है और इसे एक जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के करीब 5.10 लाख सरकारी कर्मचारी और लगभग 2.40 लाख पेंशन धारक भी इस फैसले से लाभ मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र से अधिसूचना जारी होने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके तहत आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढांचे की समीक्षा की जाएगी। वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, आयोग की अनुशंसा पहले केंद्रीय सेवाओं में लागू होगी।

डीयू के अध्ययन में खुलासा: दिल्ली की प्राकृतिक ढाल 30 साल में घटकर आधी हुई

दिल्ली । राजधानी की हरियाली और जल संरक्षण के लिए अहम नम भूमियां तेजी से गायब हो रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि बीते 30 वर्षों में दिल्ली की नमभूमि का लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा खत्म हो गया, जबकि दक्षिणी दिल्ली में यह गिरावट 97 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह अध्ययन एचसीएल टेक और टेरा ग्लोबल बिजनेस स्कूल के सहयोग से किया गया। इसमें 1991 से 2021 तक के उपग्रह आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिससे राजधानी के जल निकायों और हरित क्षेत्रों में आई गिरावट का पता चला। अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में नमभूमि क्षेत्र 2000 में 32.9 वर्ग किमी से घटकर 2022 में 30.2 वर्ग किमी रह गया। इसी दौरान, निर्मित क्षेत्र (कॉलोनियां, सड़कें, उद्योग) 485.6 वर्ग किमी से बढ़कर 825.6 वर्ग किमी हो गया, यानी लगभग 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह तेजी से बढ़ता शहरीकरण भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और जैव विविधता के लिए खतरा बन गया है। दक्षिणी

दिल्ली में नमभूमियों की हालत सबसे खराब रही। 1991 में यहां का नमभूमि क्षेत्र 0.8 फीसदी था, जो 2021 में घटकर सिर्फ 0.025 फीसदी रह गया, यानी लगभग 97 फीसदी की गिरावट आई। इसके अलावा, पूर्वी दिल्ली में यह 0.39 से घटकर 0.016 फीसदी और उत्तरी दिल्ली में 0.27 से घटकर 0.001 प्रतिशत रह गया। सबसे खास बात तो यह है कि केवल मध्य दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली ने कुछ हद तक अपने जल निकायों को संरक्षित रखा है, जिसका श्रेय यमुना नदी और बाढ़ मैदानों के संरक्षण कार्यों को जाता है। अध्ययन में कहा गया है कि नजफगढ़ झील, भलस्वा झील और हौज खास जैसी प्रमुख नमभूमियां तेजी से सिमट रही हैं।

अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

14 नवंबर को महागठबंधन का हो जाएगा सफाया

पटना । छठ के बाद बिहार विधानसभा की चुनावी धार को सभी दलों ने तेज कर दिया है। पीएम मोदी मोतीपुर चीनी मिल के मैदान में मुजफ्फरपुर की 11 और पूर्वी चंपारण की दो सीट केसरिया और पिप्रा के अलावा वैशाली की वैशाली विधानसभा सीट को भी साध रहे हैं। उनका संबोधन शुरू हो गया है। वहीं, लखीसराय में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जनता को संबोधित कर रहे हैं। वहीं, राहुल गांधी भी आज नालंदा और शेखपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज नित्यानंद राय की भी सीतामढ़ी में जनसभा होनी है। मधुबनी में तेज प्रताप यादव भी लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दरभंगा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जनसभा है। वहीं, प्रशांत किशोर दरभंगा में आज रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में देश नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो चुका है। 2005 के पहले, पूरा बिहार जंगलराज की चपेट में था। सारे उद्योग, व्यापार, ट्रेडिंग बंद हो गए थे, बस एक ही धंधा चल रहा था अपहरण और फिरौती का...आपने नीतीश बाबू के हाथ में

बिहार का शासन दिया, नीतीश बाबू ने जंगलराज को समाप्त कर दिया और बिहार में नए विकास की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि विजय कुमार सिन्हा को.. और बड़ा बना देंगे। लखीसराय मेडिकल कॉलेज का नाम श्रीकृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज होगा। राहुल गांधी ने छठ मइया का अपमान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 6 नवंबर को मतदान है, आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है लेकिन आप ऐसा सोच कर बटन मत दबाना कि आपके वोट से कोई विधायक या मंत्री बनेगा बल्कि आप ये सोच कर वोट दीजिएगा कि आपका एक-एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को विकसित बनाने के लिए है। आपका एक एक वोट जंगलराज को रोकने के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल राहुल बाबा आए और उन्होंने पीएम मोदी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन पीएम मोदी का अपमान करके उन्होंने छठी मैया का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग छठ पूजा मनाते हैं वे नाटक करते हैं। राहुल बाबा, आप छठी मैया के महत्व और आस्था को नहीं समझेंगे। न ही आपकी मां समझेंगी। आप पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की मां का अपमान किया। जब 14 नवंबर को बक्से खुलेंगे, तो (महागठबंधन) का सफाया हो जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय के केआरके हाई स्कूल मैदान स्थित मंच पर अभी पहुंचे हैं। थोड़ी देर में वह सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों आप बताएं, आप मेरे मालिक हैं। जमानत पर निकले इन कुलप्रज को बिहार लूटने की इजाजत देंगे क्या। साथियों आज हर सर्वे में एक बात खुलकर सामने आ रही कि राजद व कांग्रेस की सबसे बड़ी हार होने जा रही। एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने जा रही।

मध्य प्रदेश: पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज से क्रेन वाहनों पर गिरी, 2 लोगों की मौत

नई दिल्ली । एमपी के धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित सागौर रेलवे के निर्माणाधीन ब्रिज पर काम कर रही क्रेन अचानक पलट गई। इस दौरान एक टाटा मैजिक और एक पिकअप वाहन इसकी चपेट में आ गए। हादसे में दो लोगों की मौत की मौत हो गई। दरअसल, पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित सागौर रेलवे के निर्माणाधीन ब्रिज पर गुरुवार को सुबह साढ़े 9 बजे के लगभग ब्रिज पर गार्डर चढ़ा रही दो क्रेन दोनों छोर से गार्डर उठा रही थी। इसी वक्त सागौर की ओर लगी एक क्रेन अचानक नीचे गिर गई, जिसके चलते रास्ते से गुजर रही एक लोडिंग टाटा मैजिक और एक पिक अप वाहन उसकी चपेट में आ गए। लोडिंग टाटा मैजिक के ऊपर भारीभरकम क्रेन गिरने से उसके चालक और एक अन्य युवक बुरी तरह से दब चुके है। जो समाचार लिखे जाने तक वाहन और बचाव कार्य जारी है। अभी दोनों मृतक कौन है उनकी शिनाख्त उन्हें निकालने के बाद हो सकेगी। वहीं इस घटना में एक मां जिसके बेटे के फंसे होने की आशंका में बदहवास स्थिति में पहुंच गई है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि रेलवे पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और काम में लगी एक क्रेन अचानक पलटकर वहां से गुजर रहे एक पिकअप ट्रक पर गिर गई। उन्होंने बताया कि ट्रक में सवार दो लोगों की कुचलकर मौत हो गई। कुछ लोगों के क्रेन के नीचे फंसे होने की भी आशंका है।सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुँचे। अधिकारी ने बताया कि ट्रक में फंसे शवों को निकालने के प्रयास जारी है।

न्यायिक व्यवस्था का असंतोष सामने आया

नई दिल्ली । देश की न्यायिक व्यवस्था में पनप रहे एक असंतोष ने गुरुवार को तब खुलकर स्वर ले लिया, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि राज्य न्यायिक अधिकारियों के सेवा नियमों के निर्धारण में हैंड्स-ऑफ (असंतोष) नीति अपनाई जाए। हम आपको बता दें कि यह विवाद उस समय उभरा जब सर्वोच्च न्यायालय देशभर के जिला न्यायाधीशों के लिए समान सेवा नियमों और पदोन्नति में एकरूपता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठा रहा था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, के. विनोद चंद्रन और जॉयमाल्य बागची शामिल थे, वह इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या जिला न्यायपालिका में पदोन्नति और भर्ती के लिए सामान्य दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 227(1) के अनुसार, जिला न्यायपालिका पर पर्यवेक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है, न कि सर्वोच्च न्यायालय को। उन्होंने कहा, यह समय उच्च न्यायालयों को मजबूत करने का है, उन्हें कमजोर करने का नहीं। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी भूमिका सीमित रखनी चाहिए। राकेश द्विवेदी ने 2017 की उस पहल का भी उल्लेख किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यक्ष भर्ती जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा, उस समय भी हमने विरोध किया था, क्योंकि सेवा शर्तें और न्यायिक ढांचा हर राज्य में भिन्न है। सर्वोच्च न्यायालय न तो सेवानिवृत्ति आयु तय कर सकता है और न ही पदोन्नति का कोटा। इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य उच्च न्यायालयों की शक्तियों को छीनना नहीं है, बल्कि केवल समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहते; बस यह विचार है कि देशभर में पदोन्नति के नियमों में कुछ समानता हो।

हम आपको बता दें कि वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति का अनुपात कई बार बदला गया है। 2002 में यह 50:25:25, फिर 2010 में 65:25:10 हुआ और बाद में फिर से 50:25:25 कर दिया गया। इस असंगति ने न्यायिक अधिकारियों में असंतोष को जन्म दिया है। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था ठीक काम कर रही है।

पीएम श्री योजना पर कैबिनेट उप-समिति बना सीपीआई को धोखा दे रही वाम सरकार.., कांग्रेस नेता सतीशन का दावा

कोच्चि । केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने गुरुवार को दावा किया कि सरकार का पीएम श्री योजना की समीक्षा के लिए कैबिनेट उप-समिति बनाने का कदम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) को धोखा देने का प्रयास है। सतीशन ने कहा कि यह समिति पहले बनाई जानी चाहिए थी, न कि समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर के बाद। राज्य में भाकपा सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) का घटक दल है। सतीशन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाली वाम सरकार के उस फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसमें सहयोगी भाकपा के विरोध के बाद प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना का क्रियान्वयन रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को कहा कि सरकार ने योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए सात सदस्यीय कैबिनेट उप समिति बनाने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता सतीशन ने दावा किया कि माकपा इस तरह के फैसले से अपने गठबंधन सहयोगी भाकपा को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा, योजना और इसके क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए कैबिनेट उप-समिति समझौते पर हस्ताक्षर से पहले बनाई जानी चाहिए थी। राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष होंगे। मंत्री के राजन, पी राजीव, रोशी ऑगस्टिन, के प्रसाद, के कृष्णकुट्टी और एके ससींद्रन इसके सदस्य होंगे। योजना के क्रियान्वयन को रोकने और उप-समिति बनाने का सरकार का फैसला भाकपा के पीएम श्री के खिलाफ कड़े विरोध के बाद आया। भाकपा ने आरोप लगाया था कि यह राज्य में शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एजेंडा को लागू करने का रास्ता खोलेगा।

मल्लिकार्जुन खरगे के गृह क्षेत्र गुरमितकल में आरएसएस के रूट मार्च को मिली अनुमति

नई दिल्ली । कर्नाटक के यादगीर जिले के गुरमितकल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को पथ संचलन निकालने की अनुमति मिल गई है।

यह इलाका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का गृह क्षेत्र माना जाता है। प्रशासन ने बुधवार को आदेश जारी कर 1 नवंबर (शनिवार) को होने वाले इस मार्च के लिए मंजूरी दी। यह आयोजन आरएसएस की शताब्दी वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। यादगीर जिला प्रशासन ने पथ संचलन की मंजूरी देते समय 10 सख्त शर्तें लगाई हैं। आरएसएस के मार्च का जो रास्ता तय किया गया है, उसमें सम्राट सर्कल, एपीएमसी सर्कल, हनुमान मंदिर, मराठवाड़ी, पुलिस स्टेशन रोड, मिलन चौक और सिहिंगेरू बावी मार्केट मेन रोड से होते हुए राम नगर में इसका समापन होगा। पथ संचलन के दौरान पूरे मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहेगा। पथ संचलन की अनुमति ऐसे समय पर दी

गई है जब राज्य मंत्री प्रियांक खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, ने हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आरएसएस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि, आरएसएस सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर शाखाएं लगाकर बच्चों और युवाओं में नकारात्मक विचार भर रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकारी कर्मचारी अगर ऐसे आयोजनों में भाग लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी संगठन को कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। हाल में कुछ सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के पथ संचलन में भाग लेने पर निलंबित भी किया गया था। कांग्रेस प्रमुख, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, आठ बार गुरमितकल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि शनिवार के पथ संचलन में स्वयंसेवकों को लाठी लेकर चलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। आरएसएस ने प्रशासनिक अड़चनों के बावजूद आखिरकार इस ऐतिहासिक आयोजन की मंजूरी हासिल कर ली है, लेकिन अब नजर इस पर है कि आयोजन कितनी शांति के साथ होता है।

अभिषेक बच्चन के अवॉर्ड जीतने पर विवाद, पत्रकार ने लगाया अवॉर्ड खरीद आरोप

नई दिल्ली । हिंदी फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने हाल ही में फिल्म उद्योग में 25 साल पूरे किए हैं और लगभग 25 साल बाद, उन्होंने शूजित सरकार की फिल्म आई वांट टू टॉक (2024) के लिए 2025 में अपना पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। अभिषेक बच्चन द्वारा अपना पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीतने के कुछ हफ्ते बाद, एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर उन पर पुरस्कार खरीदने और यह दिखाने के लिए आक्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया कि वे अभी भी प्रासंगिक हैं। पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा, वह एक मिलनसार व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे यह कहने में नफरत है कि पेशेवर रूप से #अभिषेकबच्चन इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि कैसे पुरस्कार खरीदना और आक्रामक पीआर आपको प्रासंगिक बनाए रख सकते हैं... भले ही आपके करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर न हो। इस पर यूजर ने खरीदे गए अवॉर्ड्स पर भी अपना रुख साफ किया। तभी अभिषेक बच्चन ने ट्रेड एनालिस्ट को जवाब दिया और स्पष्ट किया कि उनकी जीत कड़ी मेहनत, खून-पसीने और आंसुओं का नतीजा है। इस टिप्पणी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर तुरंत ध्यान आकर्षित किया। अभिषेक बच्चन का जिक्र करते हुए, ट्रेड एनालिस्ट ने लिखा: वह भले ही एक मिलनसार इंसान हैं, लेकिन मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पेशेवर तौर पर #AbhishekBachchan इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अवॉर्ड्स खरीदना और जबरदस्त पीआर आपको प्रासंगिक बनाए रख सकते हैं... भले ही आपके करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर न हो। उन्होंने इस साल #IWantToTalk के लिए अवॉर्ड जीता... एक ऐसी फिल्म जिसे कुछ पैसे वाले समीक्षकों के अलावा किसी ने नहीं देखा। और अब मैं ये सारे ट्वीट देख रहा हूं जिनमें कहा जा रहा है कि 2025 उनका साल है। कमाल है!!

मनुस्मृति से प्रेरित सरकार की श्रम-रोजगार नीति: जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति - श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह नीति संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और सीधे-सीधे मनुस्मृति जैसी प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेने की बात कहकर देश के संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत का अपमान करती है। जयराम रमेश ने कहा, यह नीति अभी मसौदे के रूप में है, और मोदी सरकार ने इसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक सुझाव के लिए डाला है। लेकिन इस मसौदे में साफ लिखा है कि यह नीति मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से प्रेरणा लेती है। जब 1949 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तब आरएसएस ने उस पर हमला किया था और कहा था कि यह भारतीय संविधान नहीं है क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं है।

कांग्रेस की वजह से सरदार पटेल को भारत रत्न मिलने में 41 साल देरी हुई: गृह मंत्री अमित शाह

पटना । गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पटना में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 31 अक्तूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल के कारण ही आज भारत एक हो पाया। आज के भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरदार पटेल की जयंती पर 2014 से हर साल पीएम मोदी 31 अक्तूबर को केवड़िया कॉलोनी जाते हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने भव्य परेड होता है। अब गृह मंत्रालय ने तय किया है कि हर साल 31 अक्तूबर को भव्य परेड का आयोजन होगा। यह परेड देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए है। यह परेड सभी राज्यों की पुलिस बल और केंद्रीय पैरा मिलिट्री फोर्स के सम्मान में है। उनकी प्रतिमा के सामने यह परेड आयोजित होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 26 जनवरी की तर्ज पर अब हर 31 अक्तूबर को परेड का आयोजन किया जाएगा। यह परेड एकता और अखंडता का संदेश देगा। इस बार देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। इस बार 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत पर्व का

आयोजन एकता नगर में है। यह एक नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) तक यह चलेगा। 15 नवंबर को भव्य कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा। इसमें देश भर की जनजातियों के लोग शामिल होंगे। हम सभी जानते हैं कि सरदार पटेल देश के लिए एक व्यक्ति नहीं विचारधारा है। उन्होंने आजादी के आंदोलन में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 1928 का सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। उन्होंने भारत के 562 रियासत को एक कर भारत को एक किया। आज भारत का मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। जहां भी जो समस्या आई, उसका सरदार पटेल ने निवारण किया। और, पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने की मनसा को नाकाम किया। अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल की कारण लक्षद्वीप में तिरंगा फहराया गया। दुर्भाग्य की बात है कि सरदार पटेल के निधन के बाद उन्हें भुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई। सरदार पटेल के लिए न कोई समाधि बनी और न उनका कोई स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का काम किया। यह अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में किसानों से लोहा का उपयोग किया गया। आज यह प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। देश-विदेश के कई करोड़ लोग यहां आए। 31 अक्तूबर को पीएम मोदी एकता नगर में परेड को सलामी देंगे।

जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए बीजेपी विधायक

जम्मू । जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर गुरुवार (30 अक्टूबर) को सुबह ही जोरदार हंगामा हो गया. दरअसल, बीजेपी की ओर से लगातार सदन में बाढ़ राहत पर चर्चा की मांग की जा रही थी, लेकिन स्पीकर ने इनकार कर दिया. इस बात से नाराज बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए और हंगामा बढ़ता चला गया. सदन में धक्का-मुक्की होने लगी और सुरक्षाकर्मियों को मौके पर स्थिति संभालने आना पड़ा. जम्मू कश्मीर में कुछ समय पहले बाढ़ आपदा आ गई थी. बाढ़ से केंद्र शासित प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ था. इसी को लेकर बीजेपी विधायक ने इच्छा जताई थी कि विधानसभा में बाढ़ राहत को लेकर चर्चा हो, लेकिन स्पीकर ने ऐसी चर्चा से मना कर दिया।

इसके बाद बीजेपी विधायक विरोध दर्ज कराने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ नीचे आ गए, जब विधायक वेल में आने लगे, तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों में नोकझोंक शुरू हो गई और फिर मार्शल को बचाव में आना पड़ा, उन्हें विधायकों को सदन से बाहर निकालना पड़ा. इसका वीडियो भी सामने आया है. बीजेपी विधायकों द्वारा स्पीकर के फैसले के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी गई।

लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली: पीएम मोदी

आरजेडी-कांग्रेस के लिए छठी मैया की पूजा ड्रामा है, इन लोगों ने मां का अपमान किया

पटना । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की जनसभा में कहा कि आपकी इतनी भीड़ बता रही है कि इस बार फिर से एनडीए सरकार आने वाली है। बिहार में फिर से सुशासन सरकार आएगी। छठ महापर्व के बाद यह मेरी पहली जनसभा है। छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हमलोग छठ की गीत सुनकर भावविभोर हो जाते है। छठी मैया में मां की भक्ति, समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में मनाते हैं। हमलोग कोशिश कर रहे है कि यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में छठ महापर्व शामिल हो। यह सूची बड़ी जांच पड़ताल और लंबी प्रक्रिया के बाद यह सूची बनती है। हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि यूनेस्को की इस सूची में छठ महापर्व का नाम शामिल हो। अगर ऐसा होता तो हर बिहारियों को गर्व होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आपने देखा है कि आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार पूरी दुनिया में कराने में लगा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या कोई कभी चुनाव में वोट के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या बिहार यह अपमान सहन करेगा? राजद और कांग्रेस वाले कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं? उनके लिए छठी मैया की पूजा नौटंकी और ड्रामा है। वह छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। जो भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं? जो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है, उन्हें कांग्रेस और राजद वाले ड्रामा कहते हैं। यह हर उस व्यक्ति का अपमान है, जो छठी मैया में आस्था रखता है। छठ मैया के इस अपमान को बिहार सैकड़ों वर्षों तक भूलने वाला नहीं है। सैकड़ों वर्षों तक इस अपमान को छठी मैया का पूजा करने वाला नहीं भूलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा बिहार स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है। बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। एनडीए और भाजपा की पहली प्राथमिकता ही बिहार का विकास है। पीएम मोदी ने कहा कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन ही जंगलराज वालों की पहचान है। यह उनके साथियों की पहचान बन गई है। राजद और कांग्रेस वाले केवल अपने परिवार का भला करते हैं। ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते हैं। बिहार का भला करने के लिए उद्यम, उद्योग चाहिए। उद्योग के लिए जमीन,

बिजली और कानून का राज चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का रहा है, वो किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? और जिन्होंने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने भाजपा और एनडीए का सुशासन देखा है। आज बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेयरी के बड़े-बड़े प्लांट लग रहे हैं और मखाना अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। बिहार ने भाजपा-एनडीए का सुशासन देखा है। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल पूरा बिहार जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। पूरे देश भर लोग खुश हैं। लेकिन, जंगलराज में यह संभव नहीं था। जंगलराज में गाड़ियों की दुकानें बंद हो गई थी। यह इसलिए, बंद हो गए थे क्योंकि राजद के नेता अपने साथियों के साथ मिलकर शोरूम ही लूट लेते थे। अगर किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे राजद के गुंडे लग जाते थे। ऐसे जंगलराज में कोई अपनी पूंजी नहीं लगाता। राजद और कांग्रेस के ऐसे ही कुकर्मों ने लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। पलायन करने पर मजबूर कर दिया। मुजफ्फरपुर के लोग राजद सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड को कभी नहीं भूल सकते हैं। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते एक बच्चे का अपराधियों ने दिनदहाड़े अपहरण कर लिया। बदले में लाखों रुपये मांगे। जब उन्हें रुपये नहीं मिले तो गोलू के टुकड़े कर दिए। बेरहमी से उन्हें मार दिया गया। पूरे बिहार में जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं होती थी। पीएम मोदी ने कहा कि राजद के शासनकाल में करीब 40 हजार अपहरण हुए। राजद को न तब फर्क पड़ता था और न आज आपके सुख दुख से लेना देना है। राजद-कांग्रेस के ताजा प्रचार से ही उनकी नीयत का पता चलता है। चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी और इनकी हिम्मत देखिए कि यह लोग जनसभा में कैसे बता रहे हैं? इनके गानों में कट्टा, दोनाली, छुरा का जिक्र रहता है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। इनकी सोच का यह सब प्रतिबिंब है। राजद और कांग्रेस वाले बहन-बेटियों को उठाने की धमकियां दे रहे हैं। यह खेल चल रहा है। यह लोग बिहार की जनता को डरा धमका रहे हैं। इसलिए बिहार की धरती से इन्हें उखाड़ फेंक देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहेब का अपमान किया। उनकी तस्वीर का अपमान किया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहेब ने जब पीएचडी की पढ़ाई की तब उनका विषय रुपया था। वह अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े जानकार थे। इसलिए हमलोगों ने डिजिटल लेनदेन का नाम भीम रखा है।